



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262800  
CG-DL-E-01052025-262800

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1899]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947

No. 1899]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2025

का.आ.1942(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रामदेवराबेट्टा गिद्ध अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2993(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2993(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2993(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखें जाएंगे, अर्थात्: -

**“5. मानीटरी समिति.** – केन्द्रीय सरकार एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- |  |                  |
|--|------------------|
| (1) क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु   | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (2) कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि   | - सदस्य, पदेन;   |
| (3) कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि   | - सदस्य, पदेन;   |
| (4) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मैसूर के क्षेत्रीय अधिकारी   | - सदस्य, पदेन;   |
| (5) उप आयुक्त, पशुपालन विभाग, रामनगर जिला  | - सदस्य, पदेन;   |
| (6) उप आयुक्त, रामनगर जिला या उनके प्रतिनिधि   | - सदस्य, पदेन;   |
| (7) पुलिस अधीक्षक, रामनगर जिला या उनके प्रतिनिधि   | - सदस्य, पदेन;   |
| (8) प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ   | - सदस्य;         |
| (9) प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पर्यावरण या वन्यजीव या विरासत संरक्षण सहित प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि | - सदस्य;         |
| (10) सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड  | - सदस्य, पदेन;   |

(11) उप वन संरक्षक, रामनगर प्रादेशिक प्रभाग तथा वन्यजीव वार्डन, रामनगर

- सदस्य सचिव, पदेन।

**6. मानीटरी समिति के कार्य.-** (1) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों की प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।”

[फा.सं. 25/9/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक “जी”

**टिप्पण.-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 12 सितम्बर, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 2993(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30<sup>th</sup> April, 2025

**S.O. 1942(E).** — WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around the Ramadevarabetta Vulture Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2993 (E), dated the 12<sup>th</sup> September, 2017;

**AND WHEREAS**, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

**AND WHEREAS**, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

**AND WHEREAS**, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2993 (E), dated the 12<sup>th</sup> September, 2017;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2993 (E), dated the 12<sup>th</sup> September, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** — The Central Government hereby constitute a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

- |        |  |                               |
|--------|--|-------------------------------|
| (i)    | The Regional Commissioner, Bengaluru   | Chairman, <i>ex officio</i> ; |
| (ii)   | Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka   | Member, <i>ex officio</i> ;   |
| (iii)  | Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka   | Member, <i>ex officio</i> ;   |
| (iv)   | The Regional Officer, Mysuru, Karnataka State Pollution Control Board  | Member, <i>ex officio</i> ;   |
| (v)    | The Deputy Director, Animal Husbandry Department, Ramanagara District  | Member, <i>ex officio</i> ;   |
| (vi)   | Deputy Commissioner or his representative, Ramanagara District   | Member, <i>ex officio</i> ;   |
| (vii)  | The Superintendent of Police or his representative, Ramanagara District  | Member, <i>ex officio</i> ;   |
| (viii) | One expert in ecology from reputed institution or university to be nominated by the Government of Karnataka after every three years  | Member;                       |
| (ix)   | One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka after every three years | Member;                       |
| (x)    | Member, State Biodiversity Board   | Member, <i>ex officio</i> ;   |

(xi) The Deputy Conservator of Forests, Ramanagara Member Secretary,  
Territorial Division and Wildlife Warden, Ramanagara  
*ex officio.*

6. **Functions of Monitoring Committee.** — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure VI.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/9/2016-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

**Note.--** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2993 (E), dated the 12<sup>th</sup> September, 2017.